(Q) भारत में सार्वजनिक ऋण के विभिन्न स्त्रोतों का वर्णन करें।
Discuss the different kinds of sources of Public debt in India.

ऋण सार्वजनिक आय का प्रमुख स्त्रोत है यह आंतरिक तथा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त किया जाता है। Dalton ने कहा है कि "One method by which a public authority may obtain income is by borrowing." अर्थात सार्वजनिक अधिकारियों की आय का साधन सार्वजनिक ऋण भी है यही कारण है कि वर्तमान समय में सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न साधनों से ऋण प्राप्त करती है।

प्रो० Bastable ने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि "जिस प्रकार एक व्यक्ति हमेशा अपने ऋण की सहायता से अपना काम नहीं चला सकता है उसी प्रकार सरकार हमेशा ऐसी साधनों से काम नहीं चला सकती है।"

Adam Smith ने तो यहाँ तक कहा था कि "सार्वजनिक ऋण से व्यर्थ की व्यय, व्यर्थ के युद्ध, और बुरी आर्थिक परिस्थितियां पैदा होती है।" परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात को बुरा नहीं मानते है उनका विचार है कि सार्वजनिक ऋण का उपयोग यदि उत्पादक कार्यों के लिए किया जाए तो अच्छी बात है।

वर्तमान शताब्दी में आरम्भ में प्रथम विश्वयुद्ध के साथ-साथ सार्वजनिक ऋण का पूर्ण विकास हुआ अब शायद ही कोई ऐसा देश है जो ऋण न लेता हो। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से भी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है।

सार्वजनिक ऋण के मुख्य दो स्त्रोत है।

(i) आंतरिक ऋण (Internal debt)
(ii) बाह्य ऋण (External debt)

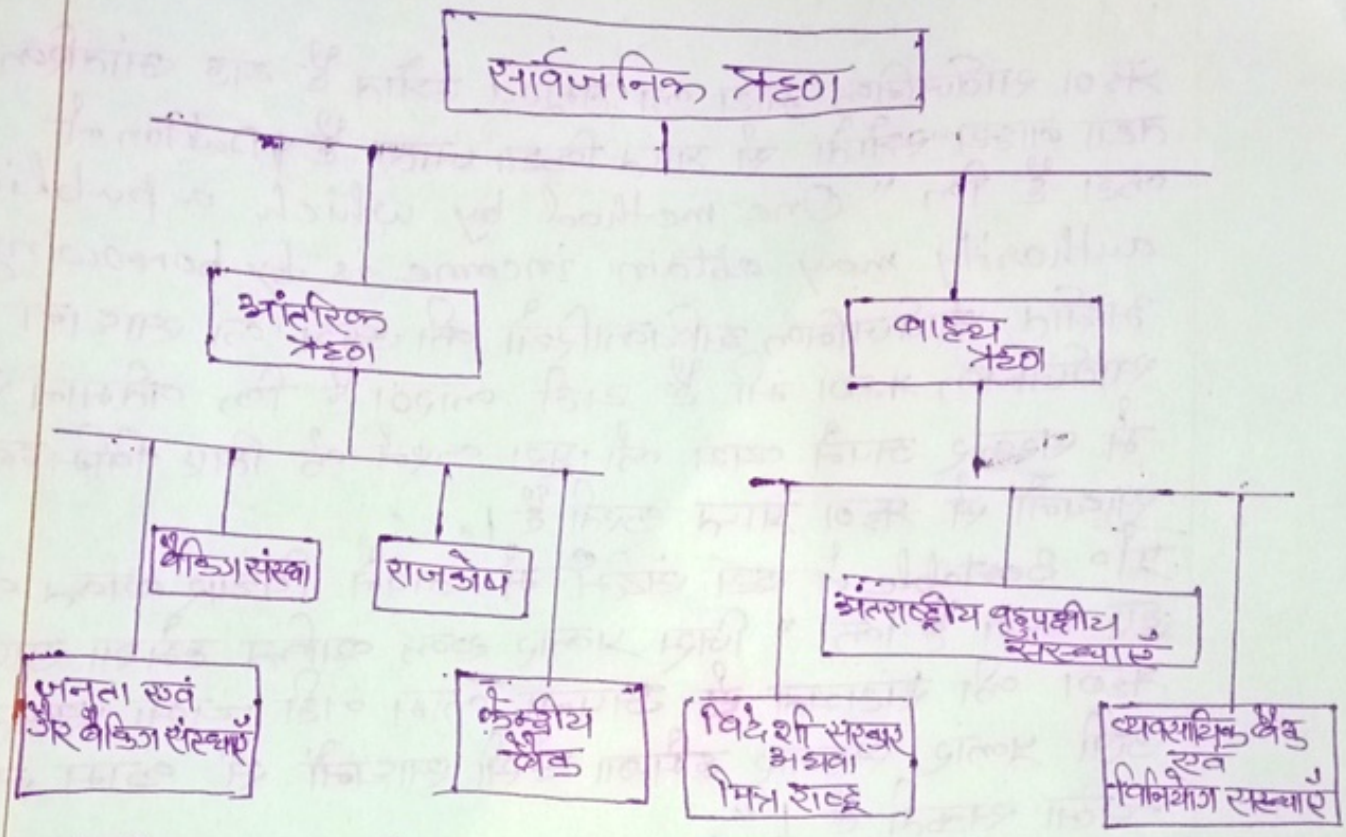

आंतरिक ऋण के चार मुख्य स्त्रोत है जो निम्नलिखित है।

(a) गैर बैंकिंग निकायो तथा जनता से प्राप्त ऋण (Browoing from non banking institution and general public)

इस तरह का ऋण गैर बैंकिंग संस्थाएँ और जनता द्वारा अपनी जमा अथवा बचत राशि से प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर इस तरह का ऋण सरकार बॉण्ड की बिक्री के द्वारा प्राप्त करती है। ये बाण्ड निश्चित समय के लिए एक विशेष ब्याज दर पर बेचे जाते है और बॉण्ड के क्रेता इन्हे ब्याज की दर के आधार पर स्वेच्छा से ग्रहण करते है यदि सरकारी बॉण्ड की योजना आकर्षित करने वाली होगी तब आम जनता तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिक विनियोग करेगें। आमतौर पर इस तरह के बॉण्ड मे ब्याज के अतिरिक्त कर मुक्ति (Tax Free) आदी की सुविधाएँ दी जाती है।

(b) Banking संस्थाओं से प्राप्त ऋण (Borrowing from bank):-
मंदी के समय विनियोग में कमी हो जाती है फलस्वरूप बैंकों के पास निष्क्रिय जमा के भंडार में वृद्धि हो जाती है इसलिए सरकार ऋण के रूप में प्राप्त इस भंडार का प्रयोग रोजगार सृजन के लिए कर सकती है इस प्रकार के ऋण से बैंक एवं सरकार दोनों को लाभ होता है। ऋण के द्वारा सार्वजनिक व्यय बढ़ने से वित्तीय प्रवाह में वृद्धि होती है जिससे राष्ट्रीय आय अनुकूल रूप से प्रभावित होती है लेकिन यदि इन संस्थाओं से बहुत अधिक मात्रा में ऋण ले लिया जाए तब निजी क्षेत्रों को ऋण पूर्ति में कमी आ जाएगी और सामान्य व्यवसायिक क्रियाएँ शिथिल हो जाएगी। दूसरी ओर स्फीति के समय इस तरह के Bond के पूर्ण कटौती के द्वारा व्यावसायिक बैंक साख का प्रसार करती है जिससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है।

(c) राजकोष से निकासी (Withdrawl from Treasury):-
सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार अपने जमा वित्तीय अवशेषों को राजकोष से निकाल सकती है साधारण तौर पर प्रतिदिन के वित्तीय गतिविधियों से कुछ धन बच जाता है जिससे सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता है सरकार आवश्यकतानुसार इस तरह की अवशेष की निकासी द्वारा अपने अवशेष को पूरा करती है।

(d) केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा निर्गमन (issue of notes by central bank):-
जब अन्य स्त्रोतों से सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता तो ऐसी स्थिति में सरकार केन्द्रीय बैंक से ऋण लेती है।

इस अवस्था में मुद्रा के माँग के अनुरूप केन्द्रीय बैंक नए नोट जारी करता है। घाटे का वित्त व्यवस्था का यह एक सर्वमान्य तरीका है। ये नोट वास्तव में ऐसा दायित्व है जिस पर सरकार को ब्याज नहीं देना पड़ता है। नए नोट जारी करने से मुद्रा का वित्तीय प्रवाह बढ़ जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में निम्न ब्याज दर पर वित्तनियोग को बढ़ावा मिलता है। मंदीकाल में सार्वजनिक ऋण से सहायता मिलती है।

बाह्य ऋण

आंतरिक स्रोतों के साथ-साथ बाह्य स्रोतों से भी ऋण प्राप्त किये जाते हैं विकासशील देशों में आंतरिक ऋण की एक सीमा होती है इसलिए अतिरिक्त वित्तीय साधनों की पूर्ति हेतु बाह्य स्रोतों का सहारा लिया जाता है।

बाह्य ऋण के तीन मुख्य स्रोत हैं।

(a) अंतराष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थाओं से ऋण (Borrowing from multilateral institution):-

इसके लिए विश्व बैंक, अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष, अंतराष्ट्रीय विकास संस्था आदी बहुपक्षीय संस्थाएँ हैं- जिनके द्वारा सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या एवं विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(b) विदेशी सरकारों से सहायता (Aid from foreign Government):-

बाह्य ऋण के दूसरा प्रमुख स्रोत विदेशी सरकारों से सहायता प्राप्त करना है। अमेरिका, जापान, जर्मनी कनाडा आदी विकसित मित्र देशों को उनके आर्थिक विकास की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर ऋण एवं अनुदान प्राप्त होते हैं इस प्रकार का ऋण दीर्घकालीन ऋण कहलाता है तथा इस पर ब्याज की दर भी कम होता है।

यह सहायता दो तरह का होता है।
(1) विशिष्ट प्रयोग के लिए सहायता
(2) स्वतंत्र प्रयोग के लिए सहायता
दूसरे प्रकार की विदेशी सहायता का उपयोगी ऋण प्राप्त करनेवाला देश अपनी इच्छा से कर सकता है जबकि पहली श्रेणी की सहायता राशि केवल उन्हीं परियोजनाओं पर खर्च की जा सकती है जिसके लिए यह सहायता ली गई है।

(C) विदेशी व्यवसायिक ऋण (Foreign Commercial Banks) :-
विदेशी व्यवसायिक ऋण, विदेशी व्यवसायिक बैंकों, विनियोग निकाय और निजी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जाती है इस तरह का ऋण अल्पकाल के लिए एवं सामान्य व्यवसायिक ब्याज दर पर दिया जाता है इसलिए यह विदेशी ऋण का सबसे महंगा स्रोत है। आमतौर पर इस तरह का ऋण तभी लिया जाता है जब अंतराष्ट्रीय संस्थाओं एवं विदेशी सरकारों से और अधिक ऋण की प्राप्ति संभव नहीं हो बाहरी स्त्रोतों से प्राप्त ऋण देश के वित्तीय साधनों में वृद्धि करता है लेकिन इसके अदायगी के समय उसी मात्रा में देश के साधनों का विकास होता है जिससे ऋण का भार बढ़ता है।

इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय आय का सार्वजनिक ऋण भी एक प्रमुख साधन है उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि यह मुख्य रूप से दो तरह के साधन अर्थात् आंतरिक तथा वाह्य साधनों से प्राप्त होता है।

ऋण प्राप्त करने का इतिहास प्राचीन है परन्तु वर्तमान परिवेश में केन्द्र अथवा राज्य सरकार विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उक्त साधनों से ऋण प्राप्त करते हैं

वास्तव मे ऋण का इतिहास यह बताता है कि प्रारम्भ मे विकसित देशों ने भी ऋण प्राप्त किये थे अत: एक अर्द्धविकसित देश खासकर जो समाजवादी समाज की कल्पना तथा आर्थिक संसाधनों के उपयोग तथा उत्पादकता मे वृद्धि करने हेतु ऋण प्राप्त करती है तो उसका प्रतिफल (return) अर्थव्यवस्था पर अच्छा होता है। फिर भी ऋण का उपयोग सीमित तथा उत्पादक कार्यों पर ही व्यय होना चाहिए।